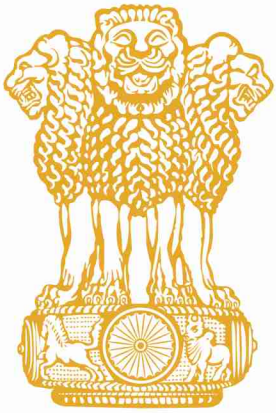

सत्यमेव जयते

पंजाब के राज्यपाल

श्री गुलाब चंद कटारिया

द्वारा

विधान सभा

में

दिनांक 6 मार्च, 2026 दिन शुक्रवार

को दिया गया

भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सदस्यगण,

1. मुझे 16वीं पंजाब विधान सभा के 12वें सत्र में इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बजट सत्र को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। विधान सभा का वार्षिक बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। अतः मुझे आशा है कि इस सत्र में होने वाले विचार-विमर्श पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए ठोस कार्यों में परिणत होंगे।

2. मेरी सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से, एक सशक्त, समावेशी और जन-संगठित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराती है, जो आज पंजाब के हर कोने में, सबसे दूरदराज के गांव से लेकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से निर्देशित, मेरी सरकार ने व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत किया है जो एक एकीकृत प्रणाली के तहत निवारक, संरचनात्मक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करता है। इस परिवर्तन के केंद्र में 881 आम आदमी क्लीनिक हैं, जो एक प्रमुख पहल है, जो तेजी से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण के एक विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में उभर रही है और जिसे पूरे देश और विदेशों से ध्यान और प्रशंसा मिल रही है। ये क्लीनिक 107 दवाइयाँ और 47 नैदानिक जाँचें निःशुल्क प्रदान करते हैं, और अब तक 4.9 करोड़ से अधिक ओपीडी विज़िट दर्ज कर चुके हैं, जिसमें 1.6 करोड़ अद्वितीय रोगी शामिल हैं। इन क्लीनिकों ने जो जनता का विश्वास

अर्जित किया है, उसका पैमाना इस उल्लेखनीय तथ्य से बाखूबी झलकता है कि मात्र तीन वर्षों में ओपीडी विज़िट में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है, जो 2022-23 में 34 लाख से बढ़कर 2025-26 में 2 करोड़ से अधिक हो गई है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 240 अतिरिक्त आम आदमी क्लीनिक शीघ्र ही चालू कर दिए जाएंगे, जिससे यह विश्वसनीय नेटवर्क पंजाब भर में और भी अधिक परिवारों तक विस्तृत हो जाएगा।

3. आम आदमी क्लीनिकों को वास्तव में विशेष बनाने वाली बात यह है कि एक आम नागरिक के लिए इनका क्या अर्थ है। कुछ समय पहले तक, लोगों को सिर्फ एक डॉक्टर को दिखाने या बुनियादी जांच कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और अक्सर अपना बहुमूल्य समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। आज, उनके पड़ोस में, उनके निकटतम आम आदमी क्लीनिक में, एक योग्य एमबीबीएस डॉक्टर मेरे पंजाब के नागरिकों की सेवा, गरिमा और देखभाल के साथ, करने के लिए तत्पर बैठा है। हर महीने, 30,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था से संबंधित जांच के लिए इन क्लीनिकों में आती हैं। यह एक ऐसी सेवा है जिसने मातृ मृत्यु अनुपात में 105 से 90 तक की महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान दिया है, जो सुरक्षित मातृत्व के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अब हर महीने 3,000 मरीजों को इन्हीं क्लीनिकों में एंटी-रेबीज टीकाकरण दिया जाता है, जिसके लिए पहले किसी दूरदराज के अस्पताल की लंबी और परेशानी भरी यात्रा करनी पड़ती थी।

4. मेरी सरकार ने जिला और उप-मंडलीय अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को उनके घरों के करीब गुणवत्तापूर्ण द्वितीयक देखभाल सेवाएं उपलब्ध हों। सार्वजनिक अस्पतालों में समर्पित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग स्थापित किए गए हैं ताकि मातृ एवं नवजात देखभाल सेवाओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो सके। ये सुविधाएं माताओं और शिशुओं को व्यापक, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं और सुरक्षित मातृत्व तथा बेहतर बाल स्वास्थ्य परिणामों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं। मेरी सरकार जिला अस्पतालों में एम.आर.आई. सेवाओं का विस्तार करके और अधिक संस्थानों में सीटी स्कैन सुविधाओं को बढ़ाकर डायगनोस्टिक नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। इससे पूरे राज्य में उन्नत चिकित्सा देखभाल तक पहुंच गहरी हो रही है। इन केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से, हम पंजाब के लोगों के लिए एक मजबूत, अधिक उत्तरदायी और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं।

5. मेरी सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल सेवाओं को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समय पर सटीक निदान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जिलों में उन्नत पीईटी स्कैन सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। ये सुविधाएं आने वाले महीनों में चालू हो जाएंगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर कैंसर रोगियों के लिए शीघ्र पहचान, स्टेजिंग और उपचार योजना में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेंगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब 'मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना' के तहत, कैशलेस कैंसर उपचार प्रदान करने वाला, देश का पहला राज्य बन गया है।यह योजना 10 सरकारी और 11 पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से प्रति रोगी 1.50 लाख रुपये (एक लाख पचास हजार) तक की वित्तीय

सहायता प्रदान करती है। अब तक, 74,000 से अधिक कैंसर रोगियों को 957 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

6. अस्पताल की क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करने और रोगी देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, मेरे राज्य ने सरकारी अस्पतालों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये के निवेश से उन्नत चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की बड़े पैमाने पर खरीद की है।

7. मेरी पंजाब सरकार ने अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती की है। 2022 से, पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए कुल 934 डॉक्टरों की भर्ती की है, जो वर्तमान में राज्य में सेवारत कुल डॉक्टरों का लगभग 25 प्रतिशत है। मेरे राज्य ने लगभग 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और पैनलिंग शुरू कर दी है, जो सबसे बड़ा विशेषज्ञ विस्तार है। तकरीबन 400 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि अतिरिक्त 500 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो रही है

8. मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब की संपूर्ण आबादी को 100% स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत, राज्य का प्रत्येक परिवार 2356 चिकित्सा और सर्जरी प्रक्रियाओं की व्यापक श्रृंखला के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य कवर का हकदार है। यह योजना पंजाब और चंडीगढ़ में सरकारी और पैनलबद्ध निजी, लगभग 900 अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण उपचार तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके। सरलीकृत दस्तावेजीकरण और नागरिक-अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ, इस

योजना को औपचारिक रूप से 22 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था। प्रत्येक पात्र नागरिक को सुविधाजनक और कैशलेस उपचार सक्षम करने के लिए एक सेहत कार्ड (हेल्थ कार्ड) जारी किया जा रहा है।

9. उन्नत तृतीयक देखभाल को मजबूत करने के क्रम में, पंजाब सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला और सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करने की योजना बनाकर एक नया मील पत्थर स्थापित करने जा रही है।

10. पंजाब सरकार ने राज्य में डायलिसिस क्षमता को दोगुना करके 4,800 तक पहुंचाकर किडनी देखभाल को मजबूत करने के लिए बड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। इस महत्वपूर्ण विस्तार ने जीवन रक्षक डायलिसिस सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है, प्रतीक्षा समय कम किया है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से आवश्यक किडनी देखभाल को रोगियों के लिए सुलभ बनाया है।

11. पंजाब सरकार अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और एम्स मोहाली में निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट सेवाएं शुरू करके, समावेशी और उन्नत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अमृतसर और पटियाला में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पहले ही सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं, जो सुनने की क्षमता बहाल करने और गहन श्रवण हानि वाले बच्चों और वयस्कों के जीवन को बदलने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ है।

12. पंजाब सरकार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एमबीबीएस/एमडी/एमएस प्रवेश बढ़ाकर और हाल के वर्षों में अन्य सरकारी

मेडिकल कॉलेजों में क्षमता का विस्तार करके मेडिकल शिक्षा को मजबूत किया है। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट में 100 एमबीबीएस सीटें, दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना में 50 एमबीबीएस सीटें और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, लुधियाना में 50 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं।

13. "सीएम दी योगशाला" मेरी सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। वर्तमान में, सभी जिलों के शहरों में प्रतिदिन लगभग 5000 पर्यवेक्षित योग सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनसे लगभग 1.5 लाख नागरिक लाभान्वित होते हैं। इस कार्यक्रम ने विशेष रूप से होशियारपुर, पठानकोट और गुरदासपुर जैसे जिलों में उल्लेखनीय जमीनी स्तर तक पहुंच हासिल की है, जहां इसकी पहुंच गांव स्तर तक विस्तारित हुई है।

14. मेरी सरकार ने पूरे राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक और दृढ़ प्रयास के रूप में 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, सुलभ और प्रभावी नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए, ओपिओइड उपयोग विकार के उपचार हेतु राज्य भर में कुल 548 ओपिओइड सहायता उपचार (ओओएटी) क्लीनिक कार्यरत हैं। इसके अलावा, उपचार और दीर्घकालिक पुनर्वास में सहायता के लिए 36 सरकारी और 177 निजी नशा मुक्ति केंद्र, साथ ही 19 सरकारी और 74 निजी पुनर्वास केंद्र कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति सेवाओं को 19 जेलों तक भी विस्तारित किया गया है, जिससे कैद व्यक्तियों के लिए देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। इन हस्तक्षेपों की शुरुआत के बाद से, 10.63 लाख से

अधिक रोगियों को पंजीकृत किया गया है और नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नेटवर्क के माध्यम से उपचार प्रदान किया गया है।

15. पंजाब सरकार ने उपचार केंद्रों को 25 से बढ़ाकर 142 करके हेपेटाइटिस देखभाल का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया है, जिसमें 23 जिला अस्पताल, 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 41 उप-मंडलीय अस्पताल, 22 एआरटी केंद्र, 27 ओएसटी केंद्र, 25 जेलें और पीजीआई चंडीगढ़ शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 4.34 लाख से अधिक लोगों की हेपेटाइटिस-सी के लिए जांच की गई है, जिसमें से 11,000 से अधिक रोगियों को निःशुल्क उपचार पर रखा गया है। इसी तरह, 3.22 लाख से अधिक व्यक्तियों की हेपेटाइटिस-बी के लिए जांच की गई है, और देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है।

16. खाद्य एवं औषधि प्रशासन पंजाब ने 2025-26 के दौरान 56,000 से अधिक लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए हैं और इसकी सशक्त प्रवर्तन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 375 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकली और गैर-अनुपालन वाली दवाएं जब्त की गई हैं।

17. जिला मोगा के दुनिके में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि जिला एसएएस नगर के जीरकपुर में दयालपुर सोढियां में इसी तरह के अस्पताल पर कार्य प्रगति पर है।

18. हाल ही में आई बाढ़ के दौरान, प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक चिकित्सा शिविर और विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाए गए, जिनमें फॉगिंग, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर संपर्क करना और दवा किट का वितरण शामिल था। 2,300 से अधिक गांवों में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से,

8 लाख से अधिक रोगियों की जांच की गई, जिससे संकट के दौरान समय पर स्वास्थ्य देखभाल और रोग की रोकथाम सुनिश्चित हुई।

19. मेरी सरकार ने इस वर्ष के दौरान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अधोसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ किया है। राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में आपातकालीन विंग को 100 बिस्तरों की क्षमता के साथ उन्नत किया गया है, जिसमें आईसीयू सुविधाएँ तथा रोगियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला में वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं में 3.05 करोड़ रुपये की लागत से बर्न यूनिट, 17.68 करोड़ रुपये की लागत से सीनियर रेज़िडेंट आवास, 15.59 करोड़ रुपये की लागत से फैकल्टी आवास, 13.53 करोड़ रुपये की लागत से जूनियर रेज़िडेंट छात्रावास तथा ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 76.33 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय भवन शामिल हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में 59.81 करोड़ रुपये और सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला में 81.80 करोड़ रुपये की लागत से ट्रॉमा सैंटरों का निर्माण प्रगति पर है। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदकोट में 24 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, 12 करोड़ रुपये की लागत से चाइल्ड ब्लॉक तथा 4 करोड़ रुपये की लागत से कैफेटेरिया भवन की परियोजनाएँ तैयार की जा रही हैं। होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 274.75 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अस्पताल की स्थापना हेतु 131.00 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा कॉलेज की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। इसी प्रकार, कपूरथला में मेडिकल कॉलेज एवं

अस्पताल के निर्माण हेतु 296.79 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है तथा निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलियरी साइंसेज़, मोहाली को 175 बिस्तरों की क्षमता तक उन्नत किए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 54.60 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया पहले से ही प्रगति पर है।

20. मेरी सरकार ने तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। गत वर्ष यकृत प्रत्यारोपण सेवाओं की शुरुआत इस उपलब्धि का सशक्त प्रमाण है। इसके साथ ही पंजाब उन विरले राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में अंग प्रत्यारोपण सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज मेरी सरकार की दूरदृष्टि तथा प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य हेतु भविष्यपरक निवेश का सजीव उदाहरण है।

21. मेरी सरकार ने "पंजाब शिक्षा क्रांति" के तहत अप्रैल 2022 से अब तक कुल 13,765 शिक्षकों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त, 234 प्राचार्यों/शिक्षा अधिकारियों के 7 बैचों को पाँच दिवसीय लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु सिंगापुर भेजा गया; 199 हेडमास्टरों के 4 बैचों को आईआईएम अहमदाबाद तथा 144 प्राथमिक कैडर शिक्षकों के 2 बैचों को तुर्कू, फ़िनलैंड भेजा गया।

22. मेरा राज्य "परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024" में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। विद्यालयों में सुरक्षा एवं स्वच्छता के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत पंजाब एक्स-सर्विसमैन कार्पोरेशन (पैस्को) के माध्यम से 2,042 में से 1,932 कैंपस मैनेजर तथा 1,378 में से 1,323 सुरक्षा

गार्ड नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी सीनीयर सेकैंडरी विद्यालयों में 1,792 चौकीदारों तथा 7876 सफाई सेवकों की भर्ती की गई है।

23. कुल 118 सरकारी विद्यालयों को अत्याधुनिक "स्कूल्स ऑफ एमिनेंस" में परिवर्तित किया जा रहा है। अब तक 29 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस जनता को समर्पित किए जा चुके हैं।

24. विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे के उन्नयन हेतु मेरी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में उच्च गति फाइबर वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए 20.0 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया है। नाबार्ड ईडीएस-39 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025–26 में 136.00 करोड़ रुपये अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कक्षों तथा रसोई, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल मैदान और बालक/बालिका शौचालयों जैसी सुविधाओं के निर्माण हेतु जारी किए गए हैं। जिससे 1,703 सरकारी विद्यालय लाभान्वित हुए हैं। "समग्र शिक्षा अभियान" के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 143.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 100.62 करोड़ रुपये अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य मरम्मत कार्यों हेतु विशिष्ट विद्यालयों को जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से कुल 2,683 सरकारी विद्यालयों को लाभ मिला है।

25. मेरी सरकार सरकारी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2025-26 के लिए प्री-प्राइमरी के 2,70,853 छात्रों, 71,940 ओबीसी छात्रों और पहली से पांचवीं कक्षा के गरीबी रेखा से ऊपर सामान्य श्रेणी के 1,27,174 छात्रों को मुफ्त वर्दी प्रदान करने के लिए 28.20 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 के

लिए छठी से आठवीं कक्षा के 48,959 ओबीसी छात्रों और छठी से आठवीं कक्षा के गरीबी रेखा से ऊपर सामान्य श्रेणी के 64,407 छात्रों को मुफ्त वर्दी प्रदान करने के लिए 6,80,19,600/- रुपये का बजट जारी किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान, सभी छात्रों को समय पर पुस्तकें वितरित की गईं। इसी वर्ष के दौरान, पंजाब राज्य के 456 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 385 स्कूलों में 'सेनेटरी पैड इंसीनरेटर मशीन' लगाने के लिए 77.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

26. शैक्षणिक वर्ष 2023–24 से कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में भाषा एवं गणित की बुनियादी दक्षताओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान सभी सरकारी विद्यालयों में 'मिशन समर्थ' चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में कक्षा-स्तर की कमजोर दक्षताओं में सुधार के उद्देश्य से 'सीईपी (कंपिटेंसी एनहैंसमेंट प्लान)' लागू किया जा रहा है। विज्ञान विषय में प्रायोगिक कौशलों के संवर्धन एवं उन्नयन हेतु राज्य के बाहर विज्ञान शिक्षकों की क्षमता-वृद्धि का कार्यक्रम भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में आयोजित किया गया है।

27. पंजाब सरकार ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर और संरचित प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में, 192 छात्रों ने जेईई मेन्स और 679 छात्रों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रदर्शन में 2024-25 में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जिसमें 265 छात्रों ने जेईई मेन्स और 847 छात्रों ने नीट योग्यता प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि 2024-25 में, जेईई मेन्स और नीट में

10-10 छात्रों ने 98वें पर्सेंटाइल से ऊपर अंक हासिल किए, जिससे उन्हें पूरे भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश मिला।

28. इस बेहतर प्रदर्शन को पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए केंद्रित शैक्षणिक हस्तक्षेपों द्वारा समर्थन मिल रहा है, जिनमें विशेष 15-दिवसीय शीतकालीन शिविर और 30-दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर शामिल हैं, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान में विषय-वार गहन कोचिंग प्रदान करते हैं, साथ ही जेईई और नीट की विशेष तैयारी भी कराते हैं।

29. सभी किसानों की जमीनों तक नहर का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने लगभग ₹787 करोड़ के निवेश से कुल 3,443 किलोमीटर नए जल-मार्गों और भूमिगत पाइपलाइनों के निर्माण की योजना बनाई है। अब तक इस कार्य के 2,650 किलोमीटर पूरे किए जा चुके हैं।

30. मेरी सरकार द्वारा 2,600 किलोमीटर नहर लाइनिंग का कार्य ₹4,557 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लगभग 880 किलोमीटर नहर लाइनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत ₹872 करोड़ है। इसमें से 331 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप 1,365 स्थानों पर पहली बार नहर का पानी पहुँचा है, जिनमें से 465 स्थानों को वर्ष 2025 में पानी प्राप्त हुआ। लंबे समय से लंबित सरहंद फीडर नहर के पुनर्लाइनिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

31. कंडी क्षेत्र के अर्ध-पहाड़ी इलाकों में पहली बार नहर का पानी उपलब्ध कराने हेतु मेरी सरकार ने 28 नई लिफ्ट योजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 15 योजनाएँ पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं। काठगढ़ और सामला पहरपुर की दो मुख्य लिफ्ट योजनाएं, जिनकी लागत क्रमशः 133 करोड़ रुपये और

86 करोड़ रुपये है, और जो 11,500 एकड़ और 2,762 एकड़ भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगी, पूर्ण होने के करीब हैं।

32. वर्ष 2025–26 के दौरान मेरी सरकार द्वारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। इस अनुदान के अंतर्गत 52,184 किसानों को ₹11.17 करोड़ की राशि वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, डीएसआर (डायरेक्ट सीडेड राइस) को प्रोत्साहित करने हेतु मेरी सरकार द्वारा किसानों को ₹1,500/- प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और वर्ष 2025–26 के दौरान कुल 23,410 लाभार्थियों को ₹35.38 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

33. राज्य में खरीफ मक्का के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, संगरूर, जालंधर और कपूरथला के 6 जिलों में शुरू की गई पायलट परियोजना के तहत, किसानों को 17,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पहली किस्त में 3743 किसानों और दूसरी किस्त में 3252 किसानों को कुल 7.88 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

34. मेरी सरकार ने इस वर्ष गन्ने के राज्य सहमत मूल्य (एसएपी) में पिछले वर्ष की तुलना में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है और आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य 416 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो देश में गन्ना किसानों को दिया जा रहा सर्वाधिक मूल्य है। पेराई सत्र 2024–25 के दौरान राज्य की नौ सहकारी चीनी मिलों द्वारा 194.66 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की

गई। गन्ना किसानों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए 07 नवंबर 2025 को ₹779.86 करोड़ की गन्ना भुगतान राशि जारी की गई।

35. धान की पराली प्रबंधन के लिए 2018-19 से अब तक सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर 1.58 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराने हेतु अब तक 394 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

36. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 33.96 करोड़ रुपये मूल्य का 84889.7 क्विंटल गेहूं का बीज और 65.15 लाख रुपये मूल्य का 620.5 क्विंटल सरसों का बीज मुफ्त वितरित किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान करने हेतु 9992 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

37. मिट्टी एवं जल संरक्षण विभाग के लिए, मेरी सरकार विभिन्न गतिविधियों की योजना बना रही है जिस के तहत एसटीपी के उपचारित अपशिष्ट जल का उत्पादक उपयोग, गांव के तालाबों का पानी, और किसानों के बीच सूक्ष्म सिंचाई और भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

38. पंजाब बागवानी विभाग कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 31,801 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा बैंकों के माध्यम से कुल ₹7,386 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा फूल बीज उत्पादक किसानों को ₹14,000/- प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जल एवं विद्युत संरक्षण को प्रोत्साहित करने के

उद्देश्य से ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से फल बागान लगाने पर ₹10,000/- प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है।

39. पंजाब में बागवानी के सतत विकास हेतु ₹1,300 करोड़ की लागत से जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से एक परियोजना प्रस्तावित है। यह परियोजना क्लस्टर स्तर पर एकीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी बागवानी फसलों को प्रोत्साहित एवं विकसित करना है, जो मौसमी परिवर्तन तथा चरम मौसम परिस्थितियों के प्रति अधिक सहनशील हों।

40. पंजाब मंडी बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए राज्य में क्षतिग्रस्त 40,103 किलोमीटर संपर्क सड़कों के उन्नयन/आधुनिकीकरण की परियोजना को ₹12,597 करोड़ की कुल लागत से क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य की 664 मंडियों में ₹197 करोड़ की लागत से कवर शेडों का निर्माण किया जा रहा है और 36 मंडियों में ₹24.42 करोड़ की लागत से सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं।

41. राज्य के 12 बाढ़-प्रभावित जिलों में पशुधन की देखभाल सुनिश्चित करने हेतु पशुपालन विभाग, पंजाब द्वारा 713 गाँवों में 492 टीमें गठित की गईं तथा 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए और 3,19,282 पशुओं का निःशुल्क उपचार किया गया, जिसके लिए विभाग द्वारा ₹37.00 लाख मूल्य की औषधियाँ उपलब्ध कराई गईं। बीमार पशुओं को उठाने हेतु पंजाब राज्य के सभी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिकों में 22 आधुनिक एनिमल लिफ्टर उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2025 के दौरान राज्य की समस्त गोवंश आबादी को लंपी स्किन डिज़ीज़ (एलएसडी) के विरुद्ध 24.27 लाख खुराकों का टीकाकरण निःशुल्क किया

गया और समस्त पशुधन आबादी को खुर पका-मुँह पका रोग (एफएमडी) के विरुद्ध 126.22 लाख खुराकों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 में गलघोंटू रोग के लिए 66.35 लाख खुराकें भी दी गईं। वर्ष 2025-26 के दौरान 10.30 लाख गायों तथा 11.01 लाख भैंसों में उच्च गुणवत्ता के सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.63 लाख आनुवंशिक रूप से उन्नत मादा बछियों का उत्पादन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1.25 लाख गायों एवं भैंसों में सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन से गर्भाधान किया गया, जिससे 4,800 उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली मादा बछियों का जन्म होने की संभावना है, जो किसानों की आय तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा।

42. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ₹1,831.91 लाख की राशि स्वीकृत की गई।

43. पंजाब सरकार ने प्रतिष्ठित किला रायपुर खेल उत्सव में बैलगाड़ी दौड़ को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में पुनर्जीवित किया है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसे सुनिश्चित बनाने के लिए, पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया, पंजाब विधान सभा द्वारा पारित किया गया, और बाद में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सहमति प्रदान की गई। यह पारंपरिक खेल बैलों की देशी नस्लों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ पंजाब की जीवंत सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस सांस्कृतिक तमाशे के प्रति उत्साह को फिर से जगाकर, सरकार का लक्ष्य न केवल पंजाबी

परंपराओं की रक्षा करना है, बल्कि राज्य के युवाओं को नशीली दवाओं के प्रभाव से दूर रखना, समुदाय की भावना और अपनी विरासत पर गर्व को बढ़ावा देना भी है।

44. पहली बार, मेरी सरकार ने पंजाब सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1961 में संशोधन करके सहकारी समितियों में संपत्ति लेन–देन के संबंध में स्पष्ट और सुदृढ़ नियामक व्यवस्था लागू की है। अब सहकारी आवास तथा अन्य अचल संपत्तियों का हस्तांतरण उचित रूप से निष्पादित कन्वेयंस डीड के माध्यम से, लागू स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण के साथ करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुधार सहकारी सदस्यों के स्वामित्व अधिकारों की सुरक्षा करता है, विवादों को कम करता है तथा राज्य के खजाने के लिए स्थायी और वैध राजस्व स्रोत सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, पंजाब सहकारी समितियाँ नियम, 1963 में नियम 28-ए को शामिल कर प्रमुख सहकारी संस्थानों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों में एक समान एवं श्रेणीबद्ध अनुशासनात्मक ढांचा भी लागू किया गया है जिससे समयबद्ध निर्णय, स्पष्ट जवाबदेही तथा अपीलों की बहुलता के निपटारे को सुनिश्चित किया गया है।

45. मेरी सरकार के नेतृत्व में, वर्ष 2025-26 के दौरान, मार्कफेड ₹26.51 करोड़ की लागत से 45,000 मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कर रहा है और मार्कफेड ने पहली बार 6.50 लाख मीट्रिक टन की ढकी हुई भंडारण क्षमता प्रदान करके कस्टम-मिल्ड चावल के भंडारण और रखरखाव का कार्य भी संभाला है। मार्कफेड ने दिसंबर 2025 तक ₹15.05 करोड़ मूल्य के 'रेडी-टू-ईट' और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

भी किया है, जिससे पंजाब के कृषि-उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विश्व स्तरीय पहुंच को मजबूती मिली है।

46. "व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0" के दृष्टिकोण के अंतर्गत मिल्कफेड पंजाब ने वित्त वर्ष 2024–25 में औसत दैनिक दुग्ध संग्रह को 21.50 लाख लीटर तक बढ़ाया है, जो वित्त वर्ष 2025–26 में और अधिक बढ़ने की दिशा में है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, मिल्कफेड ने दही, आइसक्रीम, दुग्ध पाउडर, मक्खन और पारंपरिक डेयरी उत्पादों सहित दूध उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार उत्कृष्ट संस्थानिक माध्यमों द्वारा किया है।

47. मेरे राज्य के सभी सहकारी बैंक सफलतापूर्वक उन्नत फाइनेकल-10 कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में स्थानांतरित हो गए हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण नागरिकों के लिए सहकारी बैंकिंग तेज, सुरक्षित, पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो गई है।

48. वित्तीय वर्ष 2025–26 में पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा ₹350.25 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 12 दिसंबर 2025 तक ₹220.54 करोड़ की वसूली पहले ही की जा चुकी है। वसूली प्रयासों के साथ-साथ, बैंक ने नए ऋण वितरण की प्रक्रिया भी पुनः आरंभ कर दी है, जो बैंक की पुनः सुदृढ़ होती वित्तीय स्थिति को दर्शाती है तथा राज्य में दीर्घकालिक कृषि ऋण सहायता को और मजबूत करेगी।

49. मेरी सरकार के अंतर्गत हाउसफेड पंजाब द्वारा संपत्तियों की पारदर्शी तरीके से ई-नीलामी की गई है। निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाएँ, जिनमें सेक्टर -79, मोहाली के 52 फ्लैट शामिल हैं, पूर्ण होने के निकट हैं और 31 मार्च 2026 तक आवंटी सदस्यों को इनका कब्ज़ा सौंपे जाने का लक्ष्य है।

50. वर्ष 2025–26 के दौरान रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 959 प्लेसमेंट कैंपों/रोज़गार मेलों के माध्यम से 48,912 अभ्यर्थियों को रोजगार सुविधा प्रदान की गई।

51. मेरी सरकार के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में खेलों के लिए ₹362.24 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। जिससे खेल विभाग द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के अंतर्गत 10,406 खिलाड़ियोंको खेल उपकरणों की खरीद हेतु ₹12.15 करोड़, विश्व कप 2025 जीतने वाली महिला क्रिकेटरों एवं उनके प्रशिक्षकों को ₹4.91 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, और अप्रैल 2023 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं तथा जूनियर एवं सीनियर चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1,060 खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप ₹23.1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला को वर्ष 2025–26 के लिए ₹15.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में पंजाब में 3,100 खेल मैदानों के विकास हेतु ₹190.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।

52. मेरी सरकार का उद्देश्य पंजाब को व्यापार एवं निवेश के लिए प्रथम पसंदीदा राज्य बनाना है। वर्ष 2025–26 के दौरान पूर्व एवं वर्तमान औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा विद्युत टैरिफ सब्सिडी के रूप में ₹2,892.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्टार्टअप को ₹3 लाख की दर से सीड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है और वर्ष 2022 से अब तक 191 स्टार्टअप्स को इस उद्देश्य हेतु ₹5.73 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है।

53. मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 8,261 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग ₹1,50,817 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है तथा इससे लगभग 5,31,619 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी सहित विभिन्न विदेशी निवेशकों तथा भारत के विभिन्न राज्यों के उद्योगपतियों के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही है, ताकि उन्हें पंजाब में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

54. दिसंबर 2025 में पंजाब के मुख्यमंत्री की जापान और कोरिया गणराज्य की हालिया यात्राओं ने पंजाब राज्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान किए हैं। इन वार्ताओं ने वैश्विक औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत किया है, राज्य की निवेश प्रक्रिया का विस्तार किया है, और उत्तर भारत में उच्च-प्रौद्योगिकी और मूल्य-संचालित निवेशों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में पंजाब की स्थिति को मजबूत किया है।

55. जापान यात्रा के दौरान, दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) हासिल किए गए, जिनमें वर्धमान स्पेशल स्टील्स और आइची स्टील के बीच 500 करोड़ रुपये का प्रस्तावित विनिर्माण सहयोग, और टोपपान स्पेशलिटी फिल्म्स के साथ साझेदारी में एक कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल है। टोपपान स्पेशलिटी फिल्म्स ने 300 से 400 करोड़ रुपये के विस्तार निवेश के लिए एक इच्छा पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रतिनिधियों ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ होंडा, यामाहा, फुजित्सु, एनईसी, यानमार और एयर वाटर कॉर्पोरेशन जैसे प्रमुख निगमों के साथ चर्चा की। टोक्यो और ओसाका में व्यापार रोड-शो ने पंजाब की दृश्यता को और बढ़ाया

और उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि-प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और अवसंरचना क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग खड़े किए।

56. कोरिया गणराज्य की यात्रा ने मजबूत क्षेत्र-विशिष्ट निवेश रुचि उत्पन्न की। जीएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, नोंगशिम, सनजिन और डेवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सहित निगमों ने नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, एकीकृत पशु पोषण, और उच्च-प्रौद्योगिकी औद्योगिक एवं अवसंरचना परियोजनाओं के विकास में अवसरों का पता लगाया। कोरिया डिस्प्ले इंडस्ट्री एसोसिएशन, सियोल बिजनेस एजेंसी और कोरिया सर्किट कंपनी के साथ हुई वार्ता ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर से संबद्ध विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्लस्टर में संभावनाओं का विस्तार किया। पैंग्यो टेक्नो वैली की यात्रा ने मोहाली के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

57. कुल मिलाकर, इन यात्राओं ने निवेशकों के विश्वास और फ़ालोअप ढ़ांचे को मजबूत किया है, और प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 से पहले पंजाब में प्रौद्योगिकी-गहन और नवाचार-संचालित निवेशों को आकर्षित करने के लिए एक ठोस नींव रखी है।

58. "उद्योग क्रांति पहल" के तहत सरकार ने वर्ष 2025 में 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन किया। साथ ही, सरकार ने "राईज़िंग पंजाब – सुझावों से समाधान" कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की, जो आगामी औद्योगिक एवं व्यवसाय विकास नीति के निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श है। यह परामर्श बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और एस.ए.एस. नगर में आयोजित किया गया, ताकि पंजाब के उद्योगों को अपनी बात सीधे रखने का अवसर मिल सके। मेरी

सरकार ने पंजाब राइट टू बिज़नेस (संशोधन) अधिनियम एवं नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

59. मेरी सरकार ने बढ़ी हुई भूमि लागत और मूल लागत के बकाया भुगतान के लिए 'एकमुश्त निपटान योजना', भूखंडों के क्लबिंग और डी-क्लबिंग की नीति, तथा भूखंडों के विखंडन/उप-विभाजन की नीति शुरू की है। भूखंडों के उपयोग में लचीलापन लाने और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पीएसआईईसी द्वारा वर्ष 2025 में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की नीति और रद्द किए गए भूखंडों के लिए अपीलीय प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया है।

60. मेरी सरकार ने व्यवसायों के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दूरसंचार (राइट ऑफ वेज़) नियम, 2024 को 01.01.2025 से सफलतापूर्वक लागू किया है, ताकि राज्य में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना और विस्तार को सुगम बनाया जा सके और नागरिकों एवं व्यवसायों को गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।

61. मेरे राज्य में, 01.04.2022 से 29.12.2025 की अवधि के दौरान, 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के तहत कुल 5,060 सूक्ष्म इकाइयों को उनके पहले ऋण की स्वीकृति दी गई, जिसमें ₹298.49 करोड़ की मार्जिन मनी का वितरण शामिल है।

62. मेरे राज्य में एमएसएमई को औपचारिक रूप देने के प्रयासों के तहत अब तक भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर लगभग 15.48 लाख एम.एस.एम.ई पंजीकृत किए जा चुके हैं। 30.11.2025 तक जिला स्तरीय

एम.एस.ई सुविधा परिषदों द्वारा 1,391 करोड़ रुपये मूल्य के 4,093 मामलों का निपटारा किया गया है।

63. मेरे राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोग्रेसिव पंजाब समिट 2026 के छठे संस्करण का आयोजन मार्च 2026 में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक सहायता को बढ़ावा देना है।

64. जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में कार्यान्वित की जा रही 15 बड़ी सतही जल परियोजनाओं में से 7 को चालू कर दिया है। ₹519.88 करोड़ के व्यय वाली ये परियोजनाएं 606 गांवों को कवर करती हैं और इनसे 7.37 लाख की आबादी लाभान्वित हो रही है। इनमें से एक-एक परियोजना रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और गुरदासपुर जिले में तथा दो-दो परियोजनाएं पटियाला और अमृतसर जिले में स्थित हैं। इन सभी 15 परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होगा।

65. मेरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है और इस स्थिति को सफलतापूर्वक बनाए रखा गया है, जो स्वच्छता एवं स्वच्छ जीवनशैली की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पंजाब ओ.डी.एफ प्लस दर्जा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत 11,782 गाँव ओ.डी.एफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें 2,219 मॉडल ओ.डी.एफ प्लस गाँव शामिल हैं।

66. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग ने हाल ही में 24 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में जीवाणु विज्ञान (बैक्टीरियोलॉजिकल) अनुभागों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अनुमानित लागत 6.24 करोड़ रुपये है, ताकि जीवाणु विज्ञान मानकों के लिए भी एन.ए.बी. एल. मान्यता प्राप्त की जा सके। 7 प्रयोगशालाओं

में बुनियादी संरचना कार्य एवं नए उपकरणों की स्थापना पूरी हो चुकी है तथा शेष 17 प्रयोगशालाओं में यह कार्य जून 2026 के भीतर पूरा होने की संभावना है।

67. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग पंजाब ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 897 गांवों में स्थित 346 जल आपूर्ति योजनाओं के लिए 28.98 करोड़ रुपये लागत से आई.ओ.टी-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, जिस का उद्देश्य जल आपूर्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है।

68. मेरी सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग पंजाब द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 1,35,811 एकड़ पंचायत भूमि के पट्टे से लगभग 520.54 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई है। मनरेगा योजना के अंतर्गत भी सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2025–26 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.40 लाख विकास कार्य 860 करोड़ रुपये की कुल लागत से किए गए। इस से 195 लाख से अधिक कार्य-दिवस सृजित हुए और 8.52 लाख परिवारों को आजीविका का सहारा मिला। वित्त वर्ष 2025–26 में मनरेगा योजना और पंचायत निधियों के अभिसरण से 3,200 मॉडल खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी प्रति खेल मैदान लागत 30–32 लाख रुपये है।

69. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025–26 में 74,219 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 23.12.2025 तक कुल 62,013 आवास (83.5%) स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 24,876 बाढ़-प्रभावित आवास भी शामिल हैं, जिन्हें पंजाब सरकार के विशेष प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा

स्वीकृत विशेष परियोजना के तहत कवर किया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 में अब तक कुल 150.12 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

70. मेरी सरकार ने दिसंबर 2025 तक विद्युत सब्सिडी से संबंधित सभी बकाया देनदारियों, जिनमें लंबित दायित्व भी शामिल हैं, का सफलतापूर्वक निपटान कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य सरकार द्वारा समेकित सिंकिंग फंड में ₹1000 करोड़ का योगदान किया गया है, जिससे (दिसंबर 2025 तक) इस फंड में कुल संचयी योगदान ₹10,738 करोड़ हो गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025–26 में हमारी सरकार द्वारा पहली बार गारंटी रिडेम्पशन फंड में भी ₹1000 करोड़ का योगदान दिया गया है।

71. मेरी सरकार के नेतृत्व में पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (पीआईडीबी) सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से राज्य में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें निजी निवेश एवं विशेषज्ञता के साथ सशक्त सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, पीआईडीबी द्वारा दो क्लस्टरों के अंतर्गत 15 अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) ब्लॉकों के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है जिससे सेवाओं की गुणवत्ता एवं संस्थागत प्रबंधन में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। नवांशहर एवं संगरुर में मेडिकल कॉलेजों का विकास भी पीपीपी मॉडल के तहत किया जा रहा है, जिससे चिकित्सा शिक्षा का विस्तार एवं रोजगार सृजन संभव होगा। पर्यटन क्षेत्र में, आम खास बाग सरहिंद, पिंकासिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रूपनगर, दरबार हॉल कपूरथला, रोपवे प्रोजेक्ट अमृतसर और सोहनी रेस्ट हाउस गोवा जैसी परियोजनाओं के माध्यम से विरासत स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है।

मोहाली और लुधियाना में दो कन्वेंशन सेंटरों की स्थापना से व्यापारिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा शहरी विकास को गति प्राप्त होगी। ये सभी पहलें राज्य कोष पर अनावश्यक वित्तीय भार डाले बिना तीव्र अवसंरचना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करती हैं। ₹94.81 लाख की ऑडिट फीस की प्राप्ति से वित्तीय अनुशासन एवं निगरानी व्यवस्था के सुदृढ़ होने का भी संकेत मिलता है।

72. मात्र दो वर्षों में, सड़क सुरक्षा बल (एसएसएफ) ने पंजाब में आपातकालीन प्रतिक्रिया को नया आयाम दिया है। चौबीसों घंटे कार्यरत, एसएसएफ की टीमें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी नागरिक अपने सबसे कमजोर क्षणों में सड़क पर अकेला न छूटे, प्रतिदिन 15,000 कि.मी. का गश्त करती हैं। फरवरी 2024 और जनवरी 2026 के बीच, बल ने लगभग 44,000 दुर्घटनाओं में 47,000 से अधिक लोगों की सहायता की। चाहे 19,973 व्यक्तियों को मौके पर तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान करना हो या 27,413 अन्य लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना सुनिश्चित करना हो, एसएसएफ ने साबित कर दिया है कि हर पल कीमती है। प्रतिदिन औसतन 63 लोगों की सहायता के साथ, एसएसएफ केवल एक पेट्रोलिंग इकाई ही नहीं है - यह सड़कों की संरक्षक है। भारत में मोटर दुर्घटना मुआवजे के लिए कानूनी ढांचा मोटर वाहन अधिनियम (1988) द्वारा परिभाषित किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्घटना में शामिल पक्षों के दायित्व से संबंधित सूत्र के आधार पर मामले का फैसला करता है। ऐसे मामलों में जहां अपराधी वाहन की पहचान नहीं की जा सकती है, मोटर वाहन अधिनियम में 2022 के संशोधनों ने राज्य द्वारा प्रदान की जाने

वाली अनुग्रह राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 50,000 रुपये है।

73. मेरी सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "फरिश्ते" योजना शुरू की है। यह योजना दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल, कैशलेस उपचार प्रदान करती है और घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए नेक इंसानों को 2,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करती है। इस पहल ने अब तक 600 से अधिक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करना संभव बनाया है।

74. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) डायल-112 को सुदृढ़ करने हेतु 500 अतिरिक्त वाहनों की खरीद के लिए ₹50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।

75. वर्ष के दौरान पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा 14.12.2025 को पूरे राज्य में ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए। आयोग अधिसूचना जारी होने पर 9 नगर निगमों तथा 104 नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के आम चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।

76. मेरी सरकार के नेतृत्व में, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, कपूरथला लगातार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है, जिससे वर्ष 2025-26 में 'मुख्यमंत्री विज्ञान यात्रा' के तहत 60,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में 26.90 करोड़ रुपये की स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित)

अपग्रेडेशन परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें तारामंडल का आधुनिकीकरण और नई विज्ञान गैलरियों का निर्माण शामिल है।

77. मेरी सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के निस्तारण हेतु पाँच पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएँ (आर.वी.एस.एफ) स्थापित की गई हैं। इससे पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और अनुपयुक्त वाहन सड़कों से हटेंगे। वर्ष 2025 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान इस नीति के तहत कुल 4,352 वाहन (3,946 निजी और 406 सरकारी) स्क्रैप किए गए।

78. सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ और बेहतर बनाने, छोटे गांवों को आस-पास के कस्बों से जोड़ने और राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने वर्ष 2022 से पूरे पंजाब में कुल 1,165 मिनी बस (लघु मार्ग) परमिट प्रदान करके "रोजगार क्रांति" के बैनर तले एक ऐतिहासिक और निरंतर पहल की है। इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, 19.12.2025 को एक राज्य स्तरीय समारोह में 505 परमिट वितरित किए गए। इस प्रगतिशील पहल का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण, अर्ध-शहरी और कम बस सेवा वाले क्षेत्रों में सुलभ, किफायती और कुशल परिवहन सेवाओं का विस्तार करना है। अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार और गांवों से कस्बों तक यात्रियों की सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर, इस योजना ने सार्वजनिक सुविधा को काफी बढ़ाया है। साथ ही, इस से बेरोजगार युवाओं को स्थिर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके एक सार्थक "रोजगार क्रांति" आई है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और राज्य के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देने में मदद मिली है।

79. मेरी सरकार के अंतर्गत परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से संबंधित 56 प्रकार की स्मार्ट सेवाएँ सेवा केंद्रों तथा आधिकारिक पोर्टलों www.parivahan.gov.in और www.punjabtransport.org के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय की प्राप्तियों में ₹488.67 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिससे विभाग का कुल राजस्व ₹3,426.25 करोड़ तक पहुँच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 16.63% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान, विभाग ने प्राप्तियों के रूप में ₹2,228.82 करोड़ का संग्रह किया है।

80. इस सदन को यह बताते हुए मुझे अत्यंत संतोष हो रहा है कि मेरी सरकार ने अक्तूबर–नवंबर 2025 के दौरान पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी 350वें शहीदी वर्ष का आयोजन किया। राज्य के विभिन्न भागों में नगर कीर्तन आयोजित किए गए, जिनका समापन श्री आनंदपुर साहिब में हुआ, जो स्वयं गुरु साहिब द्वारा बसाया गया था। श्री आनंदपुर साहिब में तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों ने भाग लिया। 24.11.2025 को श्री आनंदपुर साहिब में गुरु साहिब को समर्पित पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें इस सदन के सदस्यों ने उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की।

81. मेरी सरकार के अंतर्गत आदमपुर में 140 करोड़ रुपये की लागत से नया हवाई टर्मिनल पूर्ण कर लिया गया है।

82. मेरी सरकार ने इंडियन एयर फोर्स स्टेशन, हलवारा पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के बाद 161 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया,

जिसमें से 135.54 एकड़ पर हवाई अड्डा बनाया जाना है। पंजाब सरकार ने अंतरिम टर्मिनल भवन के पूर्ण होने तथा उचित सड़क संपर्क के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि शीघ्र ही उड़ानें शुरू की जा सकें। पंजाब विधानसभा ने इस हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है।

83. वर्ष 2022 की शुरुआत में, राज्य में 15 सड़कों पर 23 टोल प्लाजा थे। 03 मार्च, 2026 तक, राज्य में 13 सड़कों पर स्थित कुल 21 टोल प्लाजाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को प्रतिदिन 67.77 लाख रुपये की बचत हो रही है। उपरोक्त टोल प्लाजाओं के बंद होने से, दैनिक यात्रियों को विशेष रूप से किरतपुर साहिब-नंगल-ऊना, लुधियाना-मलेरकोटला-संगरूर और पटियाला-समाना-पातड़ां जैसे उच्च यातायात वाले गलियारों पर यात्रा लागत में प्रत्यक्ष बचत के माध्यम से काफी लाभ होने की उम्मीद है। नियमित स्थानीय उपयोगकर्ताओं, वाणिज्यिक वाहनों और परिवहन संचालकों ने परिवहन व्यय में कमी का अनुभव किया है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है और आवागमन में सुगमता बढ़ी है।

84. मेरी सरकार के तहत, नाबार्ड फंड का उपयोग करते हुए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 100 किलोमीटर लंबी सड़कों और दस पुलों को पूरा करने का प्रस्ताव है, जिस पर 94 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसमें से 52.32 किलोमीटर सड़क और आठ पुल पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और 63.95 करोड़ रुपये का खर्च किया जा चुका है।

85. वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 5054 आरबी–10 सड़क योजना के अंतर्गत 3,545 किलोमीटर योजना सड़कों के उन्नयन हेतु 2,905 करोड़ रुपये की

स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 1,470 किलोमीटर सड़कों पर 1,200 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना थी, जिन में से 720 किलोमीटर सड़कें पूर्ण की जा चुकी हैं और 423.49 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। इसी वित्त वर्ष में निर्माणाधीन 35 पुलों पर 70 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना थी, और अब तक 4 पुल पूर्ण हो चुके हैं और 56 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

86. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत 229.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का प्रस्ताव था, जिसमें से अब तक 356 किलोमीटर सड़कें और 8 पुल पूरे किए जा चुके हैं, और इस पर 131 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीआरआईएफ योजना के तहत 110 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 95 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव था, जिसमें से 40 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जा चुका है और तीन पुलों का कार्य प्रगति पर है। इस पर अब तक 78.79 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल कार्य) के तहत 33.55 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया गया है और पूर्ण व चल रहे कार्यों पर 374.95 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1784 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों पर 492 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना थी, जिसमें से 140 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है और 18.33 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

87. मेरी सरकार, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में 'ज़ीरो टालरेंस' की नीति अपनाई गई है। इसी के परिणामस्वरूप, विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब द्वारा 01.01.2025 से 31.01.2026 की अवधि के दौरान चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत 135 ट्रैप मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 20 गज़टिड अधिकारी, 134 नान-गज़टिड कर्मचारी तथा 44 निजी व्यक्तियों को अवैध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब द्वारा दिनांक 23.03.2022 को 'एंटी–करप्शन एक्शन लाइन' नंबर 95012-00200 स्थापित किया गया। इस हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर अब तक 63 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

88. जिन प्लाट धारकों द्वारा नियत समय में किस्तें जमा नहीं की जा सकीं, निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया अथवा गैर-निर्माण शुल्क जमा नहीं किया गया, उन्हें अवसर प्रदान करने हेतु मेरी सरकार ने एमनेस्टी योजना शुरू की है। यह योजना, जो 30.06.2025 को समाप्त हो गई थी, अब प्लॉट धारकों को लाभ उठाने का एक और मौका देने के लिए तिथि 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है। निजी परियोजनाओं के आवंटियों को समय पर संपत्तियों की डिलीवरी सुनिश्चित करने तथा प्रमोटरों द्वारा परियोजनाओं के डिफॉल्ट पर अंकुश लगाने हेतु पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, भूमि उपयोग परिवर्तन (सी.एल.यू) चाहने वाले प्रमोटर को परियोजना का पूर्ण स्वामित्व (100% स्वामित्व) कंपनी के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, मेगा

प्रोजेक्ट्स और पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक का विस्तार दिया गया था। प्रमोटरों को और अधिक राहत प्रदान करते हुए, ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 31.12.2025 से शुरू होकर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए एकमुश्त विस्तार दिया गया है।

89. मेरी सरकार के अंतर्गत जीएसटी संग्रह में निरंतर सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की जा रही है। अप्रैल–अक्टूबर 2025–26 के दौरान राज्य ने 15,494.03 करोड़ रुपये का संग्रह किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 13,550.62 करोड़ रुपये था—अर्थात 1,943.41 करोड़ रुपये या 14.34% की शानदार वृद्धि हुई। व्यापारिक समुदाय को लंबे समय से लंबित राहत प्रदान करने और पुराने मुकदमों के निस्तारण हेतु मेरी सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम-2025 अधिसूचित की।

90. आबकारी एवं कराधान विभाग में टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट तथा बिग-डाटा एनालिटिक्स टूल से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 333.43 करोड़ रुपये का कर एवं पैनल्टी लगाई गई है। यह टूल जी.एस.टी.आर -3 बी डिफॉल्टर्स की निगरानी हेतु अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। सतत अनुवर्तन के परिणामस्वरूप डिफॉल्टर्स द्वारा अब तक 2,009.19 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग की राज्य खुफिया और निवारक इकाई/मोबाइल विंग द्वारा वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान ₹298.51 करोड़ (इसमें से ₹98.14 करोड़ वाहनों पर और ₹200.37 करोड़ निरीक्षणों/इन्स्पेक्शन के माध्यम से वसूले गए हैं) का जुर्माना लगाया गया है।

91. मेरी सरकार के अंतर्गत एनआरआई विभाग ने विदेशों में रहने वाले पंजाबियों के लिए विदेशी दूतावासों हेतु आवश्यक दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रतिहस्ताक्षर/सत्यापन की सुविधा ई-सनद पोर्टल के माध्यम से शुरू की है। इस पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.06.2024 से अब तक कुल 55,397 दस्तावेजों को प्रति-हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

92. राज्य के सभी क्षेत्रों में समतामूलक एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 'रंगला पंजाब विकास योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी 117 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अवसंरचना तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन एवं उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर विकासात्मक अवसंरचना की आवश्यकताओं की पूर्ति 'पंजाब निर्माण कार्यक्रम' तथा मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री के अनटाइड फंड्स जैसी योजनाओं के माध्यम से की जा रही है।

93. मेरी सरकार ने पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं/अविवाहित एवं बेरोज़गार पुत्रियों व पुत्रों को दी जाने वाली पेंशन को ₹9,400 प्रति माह से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति माह कर दिया है।

94. सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्टेट पेंडेंसी डैशबोर्ड के माध्यम से विभागों में रियल-टाइम निगरानी सक्षम की गई, जिससे एक वर्ष के भीतर लंबित मामलों का प्रतिशत 14% से घटकर मात्र 0.33% रह गया और नागरिकों के अनुरोधों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित हुआ।

95. मेरे राज्य ने भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बाढ़ राहत प्रणाली शुरू की, जिसके तहत त्वरित सर्वेक्षण और मुआवज़े का सीधा ऑनलाइन अंतरण संभव

हुआ। इससे हज़ारों बाढ़-प्रभावित परिवारों को बिना देरी और बिना किसी बिचौलिए के समय पर सहायता मिली।

96. मेरी सरकार ने सेवाओं के केंद्रीकरण व सरलीकरण के माध्यम से नागरिकों की आवश्यक सेवाओं तक पहुँच का उल्लेखनीय विस्तार किया है। सभी 56 परिवहन सेवाओं को विशेष रूप से सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जिससे आर.टी.ए / आर.टी.ओ कार्यालयों के सार्वजनिक काउंटर समाप्त हुए और सेवा वितरण अधिक समान व नागरिक-अनुकूल बना। डोरस्टेप डिलीवरी कार्यक्रम को 2025 में 43 सेवाओं से बढ़ाकर 412 सेवाओं तक विस्तारित किया गया, जिससे नागरिक घर बैठे अनेक सरकारी सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं।

97. मेरी सरकार के कार्यकाल में, लुधियाना जिले के गांव गोरसियां कादर बख्श में 50 एकड़ भूमि पर 300 उच्च-जोखिम बंदियों की क्षमता वाली एक अत्याधुनिक उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में 'जेल भवन' का निर्माण एसएएस नगर में एक एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। हमने अपनी 11 केंद्रीय जेलों में आईटीआई भी स्थापित किए हैं और जेल के कैदियों के कौशल विकास के लिए विभिन्न ट्रेडों में दीर्घकालिक (1-2 वर्ष) और अल्पकालिक (3-6 महीने) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

98. मेरी सरकार के तहत, 1 अप्रैल 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से 11,063 लाभार्थियों (पंजीकृत औद्योगिक श्रमिकों) को 27.60 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

99. देश का अन्न भंडार कहलाने वाला पंजाब राज्य केंद्रीय पूल में योगदान हेतु अपनी राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) के माध्यम से गेहूँ एवं धान की खरीद करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बारदाना (गन्नी बैग), भंडारण सामग्री, कैश क्रेडिट लिमिट आदि की सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करता है। हाल ही में संपन्न खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) 2025–26 के दौरान, सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा 156.11 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी) धान की खरीद की गई, जिसके एवज में लगभग 7.38 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹37,294.68 करोड़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) राशि सीधे हस्तांतरित की गई। रबी विपणन सीजन 2025–26 राज्य में दिनांक 15.05.2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा 116.17 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई तथा 7.30 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹28,171.23 करोड़ की एम.एस.पी राशि सीधे जमा कराई गई। वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्रीय पूल में गेहूँ की कुल आपूर्ति में पंजाब राज्य का योगदान उल्लेखनीय रूप से 40 प्रतिशत रहा।

100. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.01.2023 से पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूँ का वितरण त्रैमासिक वितरण चक्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के साथ लगभग 40 लाख परिवार तथा 1.52 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं, जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

101. मेरी सरकार ने नव शुरू किए गए 'पंजाब सरकार खाद्य कार्यक्रम' के तहत सभी पात्र परिवारों (जिन्हें मुफ्त गेहूं मिल रहा है) को हर तिमाही 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर तेल और 200 ग्राम हल्दी तक मुफ्त राशन प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पंजाब के लोगों की सहायता के लिए सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध कराएगी।

102. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा) योजना के तहत 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह योजना 60:40 हिस्सेदारी वाली भारत सरकार और पंजाब सरकार की एक साझा योजना है। यह राशि अनुदान घटक के अंतर्गत पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन विश्वविद्यालय, पटियाला के लिए 'निर्माण, नवीनीकरण, उपकरणों की खरीद और सॉफ्ट कंपोनेंट्स' के माध्यम से विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए दी गई है।

103. सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, आश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना के तहत अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक ₹5212.59 करोड़ की राशि खर्च की गई है। इन योजनाओं के तहत 35.24 लाख लाभार्थी पेंशन और वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

104. राज्य में होशियारपुर, बरनाला और मानसा ज़िलों में तीन सरकारी वृद्धाश्रम चल रहे हैं। 2025-26 के दौरान, ज़िला बरनाला में ₹8.22 करोड़ की लागत से बने 72 बेड वाले वृद्धाश्रम का उद्घाटन 09.04.2025 को किया गया। इसी

तरह, जिला मानसा में ₹9.12 करोड़ की लागत से निर्मित 72-बिस्तरों वाले वृद्धाश्रम का उद्घाटन 10.01.2026 को किया गया।

105. 31.12.2025 तक, निःशुल्क बस यात्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा अनुमानित 60 करोड़ मुफ्त यात्राओं का लाभ उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, 26,066 जरूरतमंद महिलाओं को वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा एवं कानूनी सेवाएँ, पुलिस सहायता, परामर्श तथा निःशुल्क आश्रय प्रदान किया गया।

106. वित्त वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 892/1000 था, जो क्रमशः बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 922/1000 हो गया है।

107. सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग मनरेगा योजना के अंतर्गत 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से लगभग 700 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष केंद्र अगले दो महीनों में पूर्ण किए जाएंगे।

108. राज्य में बाल भिक्षावृत्ति के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु जुलाई 2024 से प्रोजेक्ट जीवनज्योत 2.0 लागू किया गया था। अब तक 1,027 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया है—जिनमें से 992 बच्चों को उनके परिवारों को सौंपा गया और 35 बच्चों को बाल गृहों में दाखिल किया गया। 38 बच्चों को प्रायोजन योजना का लाभ मिला, 349 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया, 9 बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन हुआ तथा 13 बच्चों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की गईं।

109. महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पंजाब सरकार ने मार्च 2025 में "प्रोजेक्ट हिफाज़त" आरंभ किया था। इसका मकसद महिलाओं को हिंसा से

बचाना और लिंग आधारित अपराधों पर राज्य की कार्रवाई को मज़बूत करना है। एक समर्पित 24x7 इमरजेंसी हेल्पलाइन 181 शुरू की गई है, जो मुश्किल में फंसी महिलाओं को तुरंत मदद देती है। यह प्रोजेक्ट पूरी सुरक्षा देने और जवाब देने में आने वाली कमियों को कम करने के लिए कानूनी, मेडिकल और सोशल सेवाओं को जोड़ता है। ज़रूरतमंद महिलाओं तक जल्दी पहुंचने के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसरज़ को गाड़ियां दी गई हैं, जिससे कम्युनिटी लेवल पर तेज़ी से कार्य किया जा सके। इन 181 हेल्पलाइन के ज़रिए कुल 6012 मामले मिले हैं, जिनमें से 5601 मामलों को मुश्किल में फंसी महिलाओं को मदद देकर सुलझाया गया है।

110. मेरी सरकार ने हमारे नागरिकों के लिए भूमि अभिलेखों और संबंधित सेवाओं तक पहुंच को अत्यधिक सुविधाजनक बनाने के लिए "ईज़ी जमाबंदी" पहल शुरू की है। निवासी अब व्हाट्सएप के माध्यम से जमाबंदी की नकल, उत्तराधिकार या पंजीकृत दस्तावेजों पर आधारित इंतकाल, रपट प्रविष्टियाँ, फर्द बदर और सब्सक्रिप्शन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का सहजता से अनुरोध कर सकते हैं - यह सब अपने घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या सेवा सहायकों के घर आने का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे पटवारी या तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

111. ईज़ी रजिस्ट्रेशन" परियोजना को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसने सरलीकृत रजिस्ट्री डीड प्रारूपों, रजिस्ट्री कार्यालयों के अंदर डीड ड्राफ्टिंग काउंटरों के नेटवर्क के माध्यम से, नागरिकों को अपने जिले में कहीं भी पंजीकरण कराने का विकल्प देकर, और पंजीकरण के प्रत्येक चरण में नागरिकों को सूचनात्मक व्हाट्सएप संदेश भेजकर पारदर्शी और सुगम संपत्ति

पंजीकरण सुनिश्चित किया है। इसने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है।

112. स्वामित्व योजना के तहत, जिसे पंजाब में 'मेरा घर मेरे नाम' योजना के रूप में जाना जाता है, हम उन्नत ड्रोन मैपिंग के माध्यम से औपचारिक स्वामित्व अधिकार प्रदान करके बसे हुए (आबादी देह) क्षेत्रों के निवासियों को सशक्त बना रहे हैं। यह योजना सही मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने का प्रावधान करती है, जिससे बेहतर संपत्ति रिकॉर्ड प्रबंधन और विवाद समाधान में सुविधा होगी। इस योजना के तहत, 10,037 गांवों के लिए ड्रोन उड़ान पूरी कर ली गई है और 1,572 गांवों के डिजिटल मानचित्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

113. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, फसलों, मकानों और पशुधन को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में और जान के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि के रूप में 746.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, राज्य आपदा शमन कोष के तहत बाढ़ शमन परियोजनाओं के लिए 274.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

114. प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए, उप-तहसील बनूड़ को एक उप-मंडल में अपग्रेड किया गया है और 2 नई उप-तहसीलें (लुधियाना जिले में लुधियाना नॉर्थ और होशियारपुर जिले में हरियाना) बनाई गई हैं।

115. राजस्व विभाग राज्य के राजकोष में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखे हुए है। 15.02.2026 तक, 5400 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया जा चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।

116. इस वर्ष मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है। मेरी सरकार प्रति वर्ष 7.50 लाख नागरिकों के लिए तीर्थ यात्राओं की सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत, राज्य को चार समूहों में विभाजित किया गया है। तीन समूहों के तीर्थयात्रियों को अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीरथ स्थान ले जाया जा रहा है। चौथे समूह के तीर्थयात्रियों को श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी ले जाया जाएगा।

117. राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से "श्री गुरु तेग बहादुर हरियावल संकल्प" अभियान सभी जिलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया। इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 3.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 1.11 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

118. वर्ष 2025-26 के दौरान 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' के अंतर्गत वन विभाग द्वारा 382 नानक बागिचियाँ, 52 पवित्र वन तथा 8 पर्यावरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

119. पंजाब के शहरी क्षेत्रों ने राष्ट्रीय स्वच्छता मानकों में सुदृढ़ प्रगति प्रदर्शित की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में 25 शहरों ने 'कचरा-मुक्त 1-स्टार' रेटिंग प्राप्त की है, जबकि एक शहर ने '3-स्टार' रेटिंग हासिल की है। सुरक्षित अपशिष्ट जल उपचार और पुन: उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 46 शहरों को 'वॉटर+' सर्टीफ़िकेशन प्राप्त हुआ है। स्वच्छता मानकों में भी मजबूती आई है, जिसके अंतर्गत 52 शहरों को 'ओ.डी.एफ.++', 43 शहरों को 'ओ.डी.एफ.+' और 22 शहरों को 'ओ.डी.एफ.' श्रेणी में स्थान मिला है।

120. स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत लुधियाना में ₹809.26 करोड़ की लागत से 75 परियोजनाएँ, अमृतसर में ₹686.51 करोड़ की लागत से 41 परियोजनाएँ, जालंधर में ₹722.88 करोड़ की लागत से 58 परियोजनाएँ तथा सुल्तानपुर लोधी में ₹33.77 करोड़ की लागत से 8 परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

121. शहरी परिवहन के क्षेत्र में मेरी सरकार के अंतर्गत अमृतसर में राही योजना के तहत 1,200 डीज़ल ऑटो को ई-ऑटो से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 200 पिंक ई-ऑटो वितरित किए गए हैं।

122. आईटी, ई-गवर्नेंस एवं प्रॉपर्टी टैक्स सुधार के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में अब तक ₹524 करोड़ की वसूली की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह रकम ₹486 करोड़ थी।

123. पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू किया है, जिनका मुख्य ध्यान शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर है।

124. अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लक्ष्य के तहत 2.70 लाख छात्रों को लाभान्वित करने का प्रयास है, जिनमें से अब तक 1.65 लाख छात्रों को ₹195.99 करोड़ की धनराशि (राज्य का 40% हिस्सा) शामिल है।

125. आशीर्वाद योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के

दौरान ₹242.70 करोड़ की धनराशि जारी की गई, जिससे 47,588 लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ।

126. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो ग्राम विकास पर केंद्रित है, अनुसूचित जातियों की अधिक संख्या वाले गांवों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के तहत ₹72.30 करोड़ की बढ़ी हुई धनराशि आवंटित की गई, जो 344 गांवों को कवर करती है, जिसमें विकासात्मक अंतर को पूरा करने तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए अनुदान भी शामिल हैं।

127. वर्ष 2025-26 के लिए, पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम ने 322 लाभार्थियों को 6.85 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं। इसी प्रकार, पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम (बैकफ़िंको) ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत 286 लाभार्थियों को 9.28 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

128. पंजाब सरकार और सैनिक स्कूल सोसाइटी के बीच 10.03.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार पंजाब सरकार द्वारा सैनिक स्कूल कपूरथला के 92 पेंशनरों को ₹151.28 लाख की पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ राशि प्रदान की जाएगी और साथ ही विद्यालय के संचालन एवं रख-रखाव के लिए ₹151.38 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।

129. मेरी सरकार के कार्यकाल में, राज्य द्वारा संचालित पॉलिटेकनिक कॉलेजों को 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नत किया जा रहा है (100% राज्य योजना), चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में दूसरी चरण के तहत दो और कॉलेजों (जीपीसी रोपड़ और बठिंडा) को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, सरकारी तकनीकी कॉलेजों में सभी 6वें

सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक सेमेस्टर का औद्योगिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है। साथ ही, 2025–26 से डिप्लोमा कोर्स में उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम (Entrepreneurship Mindset Curriculum-EMC) भी लागू किया गया है।

130. "युद्ध नशियां विरुद्ध" अभियान के अंतर्गत, पंजाब ने आईटीआई युवाओं के लिए जे-पाल साउथ एशिया के सहयोग से एक अग्रणी नशा-निवारण पहल शुरू की है। डॉक्यूमेंट्री आधारित, निर्देशित चर्चा पाठ्यक्रम को 246 आई.टी.आई. में लागू किया जा रहा है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से उच्च, मध्यम, और कम तीव्रता वाले 'ट्रीटमेंट ग्रुप' और 'कंट्रोल ग्रुप' में विभाजित किया गया है, ताकि प्रभाव का सटीक मूल्यांकन किया जा सके।। राज्यभर में 55 से अधिक प्रशिक्षित समन्वयकों की तैनाती की गई है, जो कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ताकि वोकेशनल विद्यार्थियों के बीच ओपिओइड-संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए निष्ठा, निरंतरता और मापनीय व्यवहारिक परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

131. भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आईटीआई में उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें सीएनसी मशीनिंग टेकनीशियन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एवं डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एवं 3-डी प्रिंटिंग, सोलर टेकनीशियन तथा इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक शामिल हैं। विभाग ने आई.टी.आई., रणजीत एवेन्यू, अमृतसर में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पंजाब के पहले 'कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (दृष्टिबाधित)'-कोपा (VI) बैच के माध्यम से समावेशी कौशल विकास का विस्तार किया है।

132. गुणवत्ता में बदलाव लाने के लिए अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, लालरू, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, नंगल और रूपनगर में मौजूद ग्यारह आई.टी.आई को सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस के तौर पर अपग्रेड किया गया है। इन सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस ने एकीकृत डैशबोर्ड, सुदृढ़ उद्योग संपर्क और प्लेसमेंट प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं, जिस के चलते 120 से अधिक कंपनियों से साझेदारी के परिणामस्वरूप 1,622 नौकरी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका औसत वेतन ₹13,190 (अधिकतम ₹30,000) रहा है। 200 से अधिक 'प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) के MoU व्यापक छात्र विकास योजनाओं तथा डिजिटल और रोजगारपरक कौशलों पर विशेष ध्यान के साथ, ये सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस कौशल विकास और उद्योग समन्वय के उच्च-प्रदर्शन केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।

133. 16 विशेष निविदाओं के माध्यम से राज्य-व्यापी आधुनिकीकरण का प्रयास चल रहा है, जिसमें सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और 3-डी मैन्युफैक्चरिंग, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लंबर, आरएसी, सोलर तकनीशियन और आईटीआई के सामान्य उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण ट्रेडों को लक्षित किया गया है। ₹40 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ, यह आईटीआई प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े मशीनरी अपग्रेड में से एक है।

134. नौकरी एवं रोजगार प्रबंधन को बेहतर ट्रैकिंग, व्यापक पहुंच और नियोक्ताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में, नवम्बर तक, 125 प्लेसमेंट मुहिमें आयोजित की गईं, जिनमें 4,004 नौकरी प्रस्ताव और 1,928 प्रशिक्षु दिए गए, जो इस क्षेत्र में सतत गति का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही, राज्य की सभी सरकारी एवं निजी आईटीआई में

उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रशिक्षण के द्वैतीय मॉडल को भी मजबूत किया गया है, जिससे 425 इकाइयों में 9,264 सीटों पर बेहतर उद्योग अनुभव उपलब्ध कराया जा सके।

135. केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण' के अंतर्गत, सरकार ने 3,122 से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को ₹265 करोड़ की रिकॉर्ड सब्सिडी स्वीकृत की है और ₹210 करोड़ वितरित किए हैं, जिनमें से 1,300 से अधिक महिला संचालित उद्यम हैं। इस वित्तीय सहायता से ₹1,181 करोड़ का नया कुल निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है। इन इकाइयों द्वारा 7,500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। इन इकाइयों ने निश्चित रूप से राज्य में उगाई जाने वाली फसलों की खाद्य श्रृंखला में मूल्य संवर्धन किया है। वर्ष 2025-26 के दौरान (14.01.2026 तक), 636 लाभार्थियों को ₹49.61 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए इस योजना को जारी रखने की अपनी सहमति दे दी है।

136. आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, न्याय विभाग ने वर्ष 2022 से 159 नए कानून अधिकारियों (120 सहायक जिला अटॉर्नी और 39 उप-जिला अटॉर्नी) की भर्ती करके अभियोजन और मुकदमों के विभाग को और अधिक मजबूत बनाया है।

137. वर्ष 2023 से 2025 के दौरान ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अमृतसर में 13.81 करोड़ रुपये की लागत से एक रिकॉर्ड रूम, मुकेरियां में 15.25 करोड़ रुपये की लागत से एक नया ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स पठानकोट में 5.80 करोड़ रुपये की लागत से कोर्ट कॉम्प्लेक्स की चौथी और

पांचवीं मंजिल और बरनाला में 13.96 करोड़ रुपये की लागत से मालखाना/रिकॉर्ड रूम, सर्विस ब्लॉक, रैंप और कनेक्टिंग कॉरिडोर का काम पूरा किया गया। त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों के लिए विशेष एनआईए अदालतें, प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुद्दों के लिए एनआरआई अदालतें और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित अपराधों के लिए पॉक्सो अदालतें स्थापित की गई हैं।

138. पर्सोनल विभाग के अंतर्गत, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' के कुल 2,706 पदों को विज्ञापित किया है, और 2,530 उम्मीदवारों की सिफारिशें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, 01.04.2022 से अब तक कुल 10,033 पदों को विज्ञापित किया गया है और 12,579 उम्मीदवारों की सिफारिशें जारी की गई हैं।

139. पर्सोनल विभाग के अधीन कार्यरत पंजाब लोक सेवा आयोग, पटियाला ने विभिन्न विभागों को ग्रुप 'ए' और 'बी' के 576 पदों के लिए सिफारिशें भेजी हैं। अब तक, 379 पदों (पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा सहित) के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं, और 129 पदों के लिए परीक्षा की तारीखें तय कर दी गई हैं।

140. पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) कृषि बिजली आपूर्ति को दिन के उजाले के घंटों में स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हमारे किसान सुरक्षित रहें और कुशलता से काम कर सकें। धान सीजन 2025 के दौरान, मेरी सरकार ने सफलतापूर्वक 83% उपभोक्ताओं यानी लगभग 11.56 लाख किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान की। इसी तरह धान

सीजन 2026 के दौरान, दिन के समय बिजली का विस्तार 88% उपभोक्ताओं यानी लगभग 12.26 लाख किसानों तक हो गया।

141. दिन के समय बिजली प्रदान करके, हम सुनिश्चित करते हैं कि किसान 'कार्यालय समय' पर काम करें। अब उन्हें कड़ाके की ठंड या खतरनाक मानसूनी रातों में रात के 2:00 बजे खेतों में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। दिन में सुरक्षित काम करने से, शारीरिक थकान, अंधेरे में काम करने के, विद्युत खतरे या वन्यजीवों का सामना, जैसे जोखिमों को समाप्त किया जा सकता है। जब एक किसान दिन के दौरान सिंचाई कर सकता है, तो वह एक 'भूमि अधिकारी' के रूप में कार्य करता है तथा पानी के प्रवाह और फसल के स्वास्थ्य की सटीकता और आसानी से निगरानी करता है।

142. मेरी सरकार पंजाब के सभी नागरिकों के लाभ के लिए विश्वसनीय, सस्ती बिजली प्रदान करने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत "रोशन पंजाब" पहल के माध्यम से ग्रिड बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान, पंजाब ने 5.7.2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मेरी सरकार ने घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं पर कोई भी पावर कट लगाए बिना धान के सीजन के दौरान कृषि उपभोक्ताओं को 8 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसके परिणामस्वरूप धान की बम्पर पैदावार हुई है। इसके अलावा, सम्मानित उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, पीएसपीसीएल में 3,000 से अधिक नई भर्तियां की गई हैं। मेरी सरकार ने एक नया 220 केवी सब-स्टेशन, छह नए 66 केवी सब-स्टेशन शुरू

करके, 67 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर और 140 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़कर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड किया है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

143. राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके, मेरी सरकार ने ट्रांसमिशन और वितरण हानि और बिजली खरीद की लागत में कमी सुनिश्चित की है। इससे पीएसपीसीएल की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और परिणामस्वरुप इसने 01.04.2025 से 30.09.2025 की अवधि के दौरान ₹2,902 करोड़ का लाभ कमाया है। मेरी सरकार की ईमानदार नीयत के कारण, हमने ₹2.48 से ₹2.748 प्रति यूनिट की दर से 2,208 मेगावाट सौर ऊर्जा सुनिश्चित की है। इसके अलावा, पूरे पंजाब में रूफटॉप सोलर (छत पर सौर) पैनल लगाकर 576 मेगावाट ग्रीन पावर जोड़ी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए बिजली शुल्क के मद में इस विभाग की कुल राजस्व प्राप्ति लगभग ₹3,105.23 करोड़ होने की उम्मीद है।

144. पछवाड़ा से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले ने प्लांट के संचालन में सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड के कोयले की तुलना में लगभग 380 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पीएसपीसीएल के थर्मल पावर स्टेशनों को अब बिजली के अनुकूलतम उत्पादन के लिए कोयले की किसी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

145. जीवन स्तर में सुधार के लिए बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। मेरी सरकार ने जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मासिक मुफ्त बिजली की योजना लागू की है। इससे लगभग 90% परिवारों को लाभ

हुआ है, जिन्हें एक बिलिंग चक्र में शून्य बिल प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा, सभी कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है। मेरी सरकार ने राज्य के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को ₹5.837 प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली प्रदान की है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

146. "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" की भावना के अनुरूप और बिजली कनेक्शन जल्दी जारी करने की सुविधा के लिए, बिजली उपभोक्ताओं को 'टेस्ट रिपोर्ट' जमा करने या उसके सत्यापन से छूट दी गई है। यह छूट सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं (एपी श्रेणी को छोड़कर) के लिए लागू है। अब ऐसे आवेदक या उपभोक्ता, जिन्हें एलटी श्रेणी के तहत नए कनेक्शन, अतिरिक्त लोड या लोड कम करने की आवश्यकता है और जिनका कुल लोड (अतिरिक्त या कम किए गए लोड सहित) 50 किलोवाट तक है, उन्हें किसी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार से टेस्ट रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने भाषण की समाप्ति से पहले, मैं इस गरिमामयी सदन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पंजाब और इसके लोगों की सेवा करेंगे और राज्य को विकास की राह पर आगे ले जाने तथा इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के मेरी सरकार के प्रयास में सहयोग करेंगे। मैं आपकी चर्चाओं की सफलता की कामना करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी 'रंगला पंजाब' को फिर से स्थापित करने के लिए कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे।

जय हिन्द